



[Signature]

भारत का याज्ञपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राप्ति । विवरण ।
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 1993/श्रावण 22, 1915
No. 155] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 1993/SAVANA 22, 1915

जन-भूतल परिवहन मंत्रालय

मंकल्प

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1993

फा. मं. आर. डो. 11034/1/93 एम बी एन.--- चुंगो, इसके योक्तिकोकरण और इसकी वर्त्तनों का पढ़ति में सुनारों आदि ने संवेदित मुद्दों को जांच करने के लिए मुख्य मंत्रियों को एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2. समिति का गठन निम्ननिवित को जानित करके लिया जायगा:—

| | |
|---------------------------------|------------|
| (1) मुख्य मंत्री, पश्चिमी बंगाल | —प्रध्यक्ष |
| (2) मुख्य मंत्री, बिहार | —सदस्य |
| (3) मुख्य मंत्री, गुजरात | —सदस्य |
| (4) मुख्य मंत्री, हरियाणा | —सदस्य |

| | |
|--|-----------|
| (5) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र | —सदस्य |
| (6) मुख्य मंत्री, उडीसा | —सदस्य |
| (7) डा. राजा चलैय्या, भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार | —सह-सदस्य |

3. श्री एस. पी. बागला, सचिव भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय समिति के सचिव होंगे।

4. समिति के विवारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

- (i) चुंगो लगाने वाले राज्यों में चुंगी लगाने और इसकी वस्तुओं में संबंधित विभिन्न समस्याओं को जांच करना,
- (ii) चुंगो के डांचे और इसकी वसूली को प्रणाली को युक्ति-संगत बनाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों को जांच करना,
- (iii) नगर तिकायों के संसाधनों को प्रभावित किए बिना चुंगो लगाने और वस्तु करने की प्रणाली को सरल करने के उपायों का सुझाव देना,
- (iv) यदि चुंगी को जारी रखा जाता है तो चुंगी लगाने और वसूल करने का प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव देना ताकि उत्पीड़न/कठिनाई, चोरी और प्राधिकार के दृष्टप्रयोग को कम किया जा सके,
- (v) चुंगो के स्वान पर कोई अन्य उत्तर/कर/शुल्क लगाने का संभावना को जांच करना ताकि इस समय चुंगी लगाने वाले राज्यों/स्थानीय तिकायों के वित्त साधनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े (इस मुद्दे को जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समिति का सिफारिशों की भी जांच की जाए)।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति जैसा आवश्यक तरीके अपने सुप्रवाही दश्तावृण कार्य करने के लिए अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी।
6. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय इस समिति के लिये सचिवालय प्रदान करेगा।
7. समिति 31 जनवरी, 1994 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को एक-एक प्रति संबंधित व्यक्तियों को भेजो जाए और इसे आम सूचना के लिए भारत के राज्यत में प्रकाशित किया जाए।

एस. पी. बागला, सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

RESOLUTION

New Delhi, the 13th August, 1993

F. No. R. T. 11034/1/93-MVL.—It has been decided to constitute a Chief Ministers' Committee to examine the issues relating to Octroi, its rationalisation and improvements in the method of its collection, etc.

2. The Committee will consist of the following :—

| | |
|--|------------------|
| (1) Chief Minister of West Bengal | Chairman |
| (2) Chief Minister of Bihar | Member |
| (3) Chief Minister of Gujarat | Member |
| (4) Chief Minister of Haryana | Member |
| (5) Chief Minister of Maharashtra | Member |
| (6) Chief Minister of Orissa | Member |
| (7) Dr. Raja Chelliah, Fiscal Adviser to the Government of India | Associate Member |

3. Shri S. P. Bagla, Secretary to the Government of India, Ministry of Surface Transport, will be the Secretary of the Committee.

4. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

- (i) To examine various problems relating to levy and collection of octroi in the States where octroi is levied;
- (ii) To scrutinise various proposals for rationalisation of octroi structure and system of its collection;
- (iii) To suggest measures for simplifying the system of levy and collection of octroi without affecting the resources meant for civic bodies;
- (iv) To suggest steps for modernisation of the system of levy and collection of octroi so as to reduce harassment|hardship, evasion and authority—if octroi were to be continued;
- (v) To examine the possibility of replacement of octroi by any other levy|tax|duty in order that finance of States|local bodies presently levying octroi are not adversely affected (The recommendations of the Committee set up by Maharashtra Government to examine this issue may also be examined).

5. The headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee will device its own procedures for its smooth and efficient functioning, as it considered necessary.
6. The Ministry of Surface Transport will provide the Secretariat for this Committee.
7. The Committee will submit its report by 31st January, 1994.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

S. P. BAGLA, Secy.